ग्रेटर फ़रीदाबाद में सरकार व बिल्डरों द्वारा लूट के नायाब हथकंडे

सीवर लाइन न होने से डेढ करोड़ का धंधा, जनरेटर की बिजली 18 रुपये यूनिट, लाखों की जबरी मेंटेनेंस

फ़रीदाबाद (म.मो.) नहर पार बसे ग्रेटर फ़रीदाबाद में फ्लैट के पूरे दाम लेकर भी खरीदारों को फ्लैट न देकर बिल्डरों ने जो अरबों रुपये की जो ठगी मारी है वह तो है ही, फ्लैट लेकर बसे लोग़ों से भी ठगी व ब्लैकमेलिंग बड़े पैमाने पर चल रही है। आज के आधुनिक युग में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई नया शहर बिना सीबर लाइन के भी बसाया जा सकता है। परंतु ग्रेफ़ा एक ऐसा आधुनिक शहर, देश की राजधानी से मात्र 20 किलोमीटर के फ़ासले पर, है जिसमें सीवर लाइन ही नहीं है। सीवर के विकल्प के तौर टैंकरो का सहारा ठीक उसी तरह लिया जा रहा है जैसे स्लम व अनाधिकृत बस्तियों में लिया जाता है। यानी सोसायटियों में सीवेज टैंक बनाये गये हैं जिनमें से ट्रैक्टर टेंकर मशीन द्वारा सीवेज निकल कर जहां-तहां फ़ैला देते हैं। इसकी वजह से क्षेत्र में कई छोटे-छोटे जोहड़ जैसे बन गये हैं जो न केवल वायु प्रदूषित कर रहे हैं बल्कि भू-जल को भी प्रदूषित कर रहे हैं।

विदित है कि बाहरी सड़कें व मुख्य सीवर लाइन बिछाने का कार्य हरियाणा सरकार के 'हूडा' विभाग का है। इसके लिये सरकार बिल्डर से और बिल्डर फलैट अथवा प्लॉट खरीददार से ईडीसी के नाम पर मोटी वसूली करते हैं। ग्रेफ़ा में बिल्डरों ने अपने ग्राहकों से 8000 करोड़ की वसूली करीब 10 वर्ष पूर्व कर ली थी जिसमें से सरकार के पास 3500 करोड़ पहुंची; शेष 4500 करोड़ को बिल्डर डकार गये। इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार ने 3500 करोड़ में से मात्र 800 करोड़ ही बाहरी विकास पर खर्च किये बाकी को सरकार डकार गयी अथवा रोहतक या अन्यत्र कहीं विकास पर खर्च दिये। ऐसे में सीवर और सड़कों के काम का अटकना-लटकना स्वाभाविक है जिसके लिये हरियाणा सरकार पूरी तरह जिम्मेवार है।

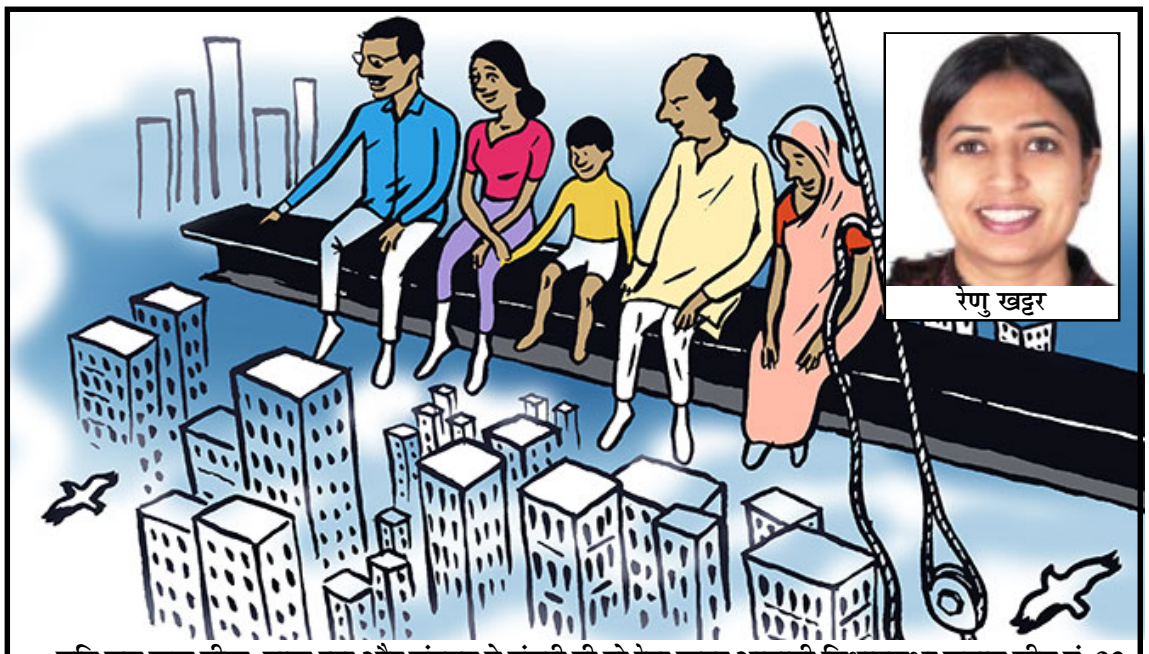

यदि सब कुछ ठीक-ठाक रहा और संगठन ने मंजूरी दी तो रेणु खट्टर आगामी विधानसभा चुनाव सीट नं. 89 यानी विपुल गोयल वाली सीट से चुनाव लडेंगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि विधायक बनने के बाद यह जरूरी नहीं कि उनके आदेश चलने लगेंगे और सारी समस्यायें चुटकी बजाते ही हल हो जायेंगी। विधायक बनने से वे जनता की अधिकृत प्रतिनिधि होकर संघर्ष लड़ेंगी। यदि हार भी गयी तो जितने वोट उन्हें मिले होंगे उतने लोग़ों की तो वह अधिकृत प्रतिनिधि हो ही जायेंगी। इससे उनके संघर्ष करने की शक्ति बढेगी। उनका मूल मंत्र है संघर्ष बिना गुजारा नहीं, बिना लड़े कुछ मिलता नहीं, इसलिये हम लड़ेंगे साथियों।

इस क्षेत्रवासियों के लिये संघर्ष में जुटी रेणु खट्टर ने इस संवाददाता को बताया कि मात्र 44 किलोमीटर लम्बी सीवर लाइन डलनी है जिसके डालने में न सरकार की रुचि है न स्थानीय नेताओं की, क्योंकि लाइन के न डलने से करीब डेढ करोड़ मासिक का कारोबार टेंकर माफ़िया कर रहा है वह भी मात्र 30 सोसायटियों से। माफ़िया के तमाम लोग सदैव सत्तारुढ दल के साथ रहते हैं। आज भाजपा के रंग में रंगे हैं तो पहले कांग्रेसी झंडा उठाये हुए थे। इनके मनमाने रेट हैं और जहां भी चाहे टैंकर खला देते हैं। यदि कोई टैंकर सस्ते में काम करना चाहे तो उसे गुंडागर्दी से रोक देते हैं। इस लूट में से कुछ हिस्सा आरडब्लूए चलाने वाले अथवा मेंटेनेंस वसूलने वाले बिल्डर भी वसूलते हैं। अपना धंधा कायम रखने के लिये ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि सीवर लाइन डले। इसके लिये आवश्यक भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार व किसानों के बीच नूरा-कुश्ती का नाटक चल रहा है। गूजर बाहुल क्षेत्र होने के चलते स्थानीय सांसद कृष्णपाल गूजर व कांग्रेसी विधायक ललित नागर तो इस अपवित्र गठजोड़ के साथ हैं ही, उद्योग मंत्री भी गूजर वोटरों को नाराज़ करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते।

मेंटेनेंस के नाम पर भी बिल्डर सोसायटी वासियों से मोटी लूट करने में जुटे हैं। यानी फ्लैट बेच कर भी असल मालिक बिल्डर ही बने हुए हैं और असल मालिकों की स्थिति किरायेदार सरीखी बना रखी है। मेंटेनेंस के नाम आठ-आठ हज़ार तक मासिक वसूली की जा रही है। इसका एक उदाहरण प्राणायाम सोसायटी है। इसमें कुल 854 घर बसे हुए हैं। इन सब से हर महीने 65 लाख की अवैध वसूली दादागिरी के बल पर लगातार बरसों से होती आ रही है। इतना ही नहीं, इतनी बड़ी रकम देने के बावजूद यहां के निवासियों को वे सब सुविधायें नहीं मिल पा रही जिनके वे हकदार हैं। जनरेटर सैट की बिजली के 18 रुपये प्रति यूनिट वसूले जाते हैं। कुल मिला कर सोसायटी से हर तरह की लूट बिल्डर कर रहे हैं जबकि नियमानुसार फ्लैट बेचने के बाद बिल्डर का कोई ताल्लुक सोसायटी से नहीं रह जाता।

पिछले दिनों एक और मजे की बात यह भी सामने आई जब सीवर द्वारा प्रदूषण के मामले को लेकर एनजीटी ने सोसायटियों को सील करने व उनके बिजली क्नेक्शन काटने के आदेश दे दिये। जाहिर है इस तरह के आदेश से न तो बिल्डरों का कुछ बिगड़ने वाला था न सरकार का, जो फ्लैटवासियों से पैसा लेकर डकार चुके थे। यानी यह कहर भी उन्हीं पर टूटा जिन्हें बिल्डरों व सरकार ने मिल कर ठगा था।

सरकार की इन्हीं जनविरोधी नीतियों से तंग आकर व स्थानीय राजनेताओं की बेरुखी देख कर यहां के लोग़ों ने संगठित होकर संघर्ष का रास्ता पकड़ा। हज़ारों नर-नारी एक जुट हो कर सड़कों पर उतरे, लम्बे-लम्बे जुलूस निकाले ज़िलाधिकारियों मंत्रियों व विधायकों के दरवाजों पर धरने प्रदर्शन किये। इसके बदले इन सबसे जनता को झांसे व झूठे वायदे दिये। जनता के वोट पाकर उनके प्रतिनिधि बने नेताओं का यह रवैया देखकर ग्रेफ़ा निवासियों ने राजनीतिक शक्ति अपने हाथों में लेने का संकल्प किया है। इसके सांगठनिक स्तर पर तैयारियां पूरे जोर-शोर से चल रही हैं।

संसदीय चुनाव में भाजपा उम्मीदवार कृष्णपाल नालायक विधायकों पर निर्भर रहें तो कैसे

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

फ़रीदाबाद संसदीय क्षेत्र में कुल 9 विधानसभा सीट हैं। इनमें से फ़रीदाबाद बडखल व बल्लबगढ तो सीधे-सीधे भाजपा के पास है और पृथला व एनआईटी की सीटें क्रमश: बसपा व लोकदल के पास होते हुए भी परोक्ष रूप से भाजपा की गोद में बतौर शरणार्थी हैं।

भाजपा के संसदीय उम्मीदवार के लिये वोट जुटाने एवं जिताने का पूरा दायित्व इन्हीं के नाजुक कंधों पर है। कंधे नाजुक इसलिये हैं कि इनके खुद के कर्मकांड बीते पांच साल में ऐसे रहे हैं कि आगामी विधान सभा चुनाव में इनका अपना बंटाधार होना तय है। बड़खल विधान सभा क्षेत्र से विधायक सीमा त्रिखा ने अपने क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके बूते वे जनता से वोट मांग सकें। जिस बड़खल झील को वह लबालब भरने की बात कर रही थी उसे वे सीवर के गंदे पानी से भी नहीं भरवा पाई। हां इसको भरने के लिये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट व पाइप लाइन बिछाने के लिये करोड़ों रुपये के बजट की कहानियां अपने भाषणों द्वारा जरूर परोसती रहीं। जबकि इस झील को बरसाती पानी से भरना बहुत ही सरल एवं सस्ता था, परन्तु सस्ता और सरल काम तो करना ये लोग जानते नहीं। क्योंकि उससे कोई खास लूट कमाई नहीं हो पाती।

सीमा त्रिखा के क्षेत्र में ज़िले का सबसे बड़ा सरकारी बीके अस्पताल है। इस अस्पताल में सीमा झाड़ू-पोचा तो लगा सकती हैं परन्तु इसमें डॉक्टरों व अन्य स्टाफ़ के अलावा पर्याप्त उपकरणों व दवाओं की व्यवस्था नहीं करा पाई, और तो और रैबीज़ जैसे साधारण टीकों की व्यवस्था तक नहीं करा पाई। इस अस्पताल के साथ-साथ क्षेत्र के कायम अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों की दुर्दशा का आलम यह है कि आये दिन गर्भवती महिलाओं को अस्पताल के दरवाजे पर, ऑटो में अथवा पेड़ के नीचे बच्चा जनना पड़ता है। अस्पताल में तैनात डॉक्टरनी तो रात की ड्यूटी में आना ही पसंद नहीं करती और स्टाफ़ ही दिल्ली के लिये रैफ़र कर देता है। ईएसआई कवर्ड श्रमिक वर्ग भी बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में रहता है। उनके लिये बनी ईएसआई डिस्पेंसरियों की दुर्दशा की ओर झांकने का समय तो विधायक महोदया को हो ही नहीं सकता क्योंकि ईएसआई कार्पोरेशन केन्द्र सरकार के अधीन है। लेकिन विधायक को शायद यह ज्ञान नहीं है कि इन्हें चलाने का पूरा दायित्व हरियाणा सरकार का है जिसके लिये पूरा खर्च ईएसआई कार्पोरेशन करती है। इसके अलावा केन्द्र सरकार भी तो इन्हीं की अपनी पार्टी की है।

तमाम सरकारी स्कूलों की हालत निहायत खस्ता है। उनमें न तो पर्याप्त स्टाफ़ है न आवश्यक अध्ययन सामग्री। बिजली कनेक्शन कहीं हैं भी तो वे बिल न भरने के चलते कटे पड़े हैं। पंखे अव्वल तो हैं नहीं जहां हैं भी तो चलने लायक नहीं। शौचालय भी न के बराबर है, जहां हैं भी वे सफ़ाई के अभाव में इस्तेमाल करने लायक नहीं पीने का पानी तक भी बच्चे घर से लेकर आते हैं। इन स्कूलों की परिस्थितियां ऐसी बना दी गयी हैं कि जिसकी थोड़ी सी भी क्षमता है वह अपने बच्चे को सरकारी की अपेक्षा प्राइवेट स्कूल में ही भेजने का प्रयास करता है। उधर सरकार को, बच्चे कम होने के चलते स्कूल बंद करने का बहाना मिल जाता है। ऐसा भी नहीं कि सीमा त्रिखा ने बीते पांच साल में कोई काम ही नहीं किया। वे अपने खाते में सैंकड़ों काम गिनवाती हैं। जनता को बहकाने के लिये, नगर निगम जो भी सड़क या नाली बनाती थी उसका उद्घाटन करने हेतु ये नारियल फ़ोड़ने पहुंच जाती रही हैं। नगर निगम को हिदायत थी कि उनके फ़ोन के बगेर किसी की सीवर, स्ट्रीट लाईट अथवा पानी की समस्या हल न की जाय। जाहिर है ऐसे में लोग अपनी इन छिट-पुट समस्याओं के लिये इन्हें फ़ोन करते और सीमा उनका काम कराकर उन पर एहसान करती रही।

अवैध कब्ज़े व निर्माण करने वाले बिल्डरों की भरपूर मदद करती रही। इतनी मदद कि इलाके के लोग इन्हें बिल्डरों का हिस्सेदार तक मानने लगे। अवैध शराब बेचने व थाने की दलाली करने वाला टंडन इनका पारिवारिक सदस्य जैसा बना है। मुख्यमंत्री खट्टर के रोड शो में उसे वाहन पर ऐसे बैठा कर घुमाया गया मानो वह शहर का बड़ा मौजिज शहरी हो। उसके अपराधों के लिये पुलिस आयुक्त तक भी सीमा पैरवी कर चुकी हैं।

इतने 'बढ़िया-बढ़िया' काम करने के आधार पर सीमा कितने वोट अपने क्षेत्र से दिला पायेंगी यह तो समय ही बतायेगा। अन्य तीन सत्तारूढ विधायकों के कार्यकलाप भी सीमा से कोई भिन्न नहीं हैं। बल्लबगढ के विधायक मूल चंद के सेक्टर 8 स्थित घर के निकट बने 200 बेड के अस्पताल में चल रहे 50 बेड की दुर्दशा देखने की इन्होंने कभी जरूरत ही नहीं समझी। इसके विपरीत वे बल्लबगढ में 200 बेड का नया अस्पताल बनवाने की घोषणा करते हैं। इसी से सम्बन्धित एक सवाल के जवाब में मूल चंद जी ने फ़र्माया कि 'वह तो ईएसआई कवर्ड लोग़ों के लिये है, आम लोग़ों के लिये थोड़े ही है।'' जिस अल्पज्ञ विधायक को इतना भी ज्ञान नहीं कि उसके क्षेत्र के करीब 3 लाख परिवार जो वोटर भी हैं, ईएसआई कवर्ड हैं। इन सभी के वेतन का साढे 6 प्रतिशत ईएसआई हर माह काट लेती है उसके बावजूद उन्हें इलाज के लिये भटकना पड़ता है। लेकिन मूल-चंद जैसे के लिये यह कतई कोई मुद्दा नहीं है। इनके लिय तो बस एक ही मुद्दा है भारत माता की जय, राष्ट्रवाद, हिन्दुत्व आदि-आदि।

वैसे ये सारी सच्चाई कृष्णपाल भी खूब जानते समझते हैं। जब वे अपने ही किये हुए तथाकथित कामों पर वोट नहीं मांग सकते तो बेचारे विधायकों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे में ले दे कर इन सब को बेचारे मोदी के नाम का ही सहारा है। वैसे जागरूक एवं समझदार नागरिक बखूबी समझते हैं कि मोदी ने ही बीते पांच साल में कितने पहाड़ तोड़े हैं।